प्रकाशन का 44 वां वर्ष
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक
ई-पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
www.facebook.com/shailshamachar
वर्ष 44 अंक-35 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 26-02 सितम्बर 2019 मूल्य पांच रूपए

कर्ज के आंकड़ों पर जयराम को मुकेश की खुली चुनौती

शिमला/शैल। मानसून सत्र के अन्तिम दिन विधानसभा में विधायक रमेश धवाला और जगत सिंह नेगी तथा राजेन्द्र राणा का प्रश्न था कि गत

तीन वर्षों में दिनांक 31-7-2019 तक प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक तथा अन्य ऐजैन्सीयों से कितना ऋण लिया है (क) किन योजनाओं हेतु कितनी राशी ऋण के रूप में स्वीकृत हुई है। (ख) स्वीकृत ऋण में से कितनी धन राशी कहां और किस योजना पर खर्च हुई ब्योरा दें। इस प्रश्न के उत्तर में सदन में रखी गयी जानकारी के मुताबिक 2017-18 में कुल ऋण 5200.13 करोड़ लिया गया जिसमें से 3099.68 करोड़ वापिस कर दिया है। 2018-19 में 4932.03 करोड़ लिया और 3177.41 करोड़ वापिस किया गया तथा 2019-20 में (31-7-2019) में 1197.69 करोड़ लिया और 240.42 करोड़ वापिस किया। इसके मुताबिक तीन वर्षों में 11329.85 करोड़ का ऋण लिया गया जिसमें से 6517.51 करोड़ वापिस करने के बाद 4812.34 करोड़ का ऋण शेष बचा है।

ऐसा ही एक सवाल बजट सत्र के दौरान भी मुकेश अग्निहोत्री और रामलाल ठाकुर ने पूछा था। इसके जवाब में बताया गया था कि 3451 करोड़ का कर्ज लिया गया है जिसमें से 3000 करोड़ खुले बाजार से लिया गया। इसमें से कुछ कर्ज वापिस करने के बाद 1838.75 करोड़ का ऋण शेष बचा है। इन दोनों सूचनाओं को इकट्ठा रखने के बाद 6600 करोड़ से अधिक का ऋण इस सरकार के अब तक के कार्यालय में लिये गये ऋण में से अभी वापिस दिया जाना बाकी है। लेकिन मुख्यमन्त्री ने सदन में आये इन आंकड़े को नज़रअन्दाज़ करते हुए यह जानकारी दी कि उनकी सरकार ने केवल 2711 करोड़ का ऋण लिया है। मुख्यमन्त्री के इस दावे को नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में खुली चुनौती देते हुए आरोप लगाया है कि मुख्यमन्त्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। सरकार द्वारा स्वयं सदन में रखे इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि मुकेश अग्निहोत्री की चुनौती बिना आधार के नही है।

(क) गत तीन वर्षों में दिनांक 31-07-2019 तक प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं से लिये गये ऋण का ब्यौरा :-

(राशि करोड़ रूपये में)

ऋण का नाम	2017-18			2018-19			2019-20 (31-07-2019)			कुल		
	उठाये गये ऋण	वपिस किये गये ऋण	शुद्ध ऋण	उठाये गये ऋण	वपिस किये गये ऋण	शुद्ध ऋण	उठाये गये ऋण	वपिस किये गये ऋण	शुद्ध ऋण	उठाये गये ऋण	वपिस किये गये ऋण	शुद्ध ऋण
बाज़ारी ऋण	4600.00	2049.01	2550.99	4210.00	2101.90	2108.10	1100.00	-	1100.00	9910.00	4150.91	5759.09
नाबार्ड	500.00	350.00	150.00	625.76	391.10	234.66	47.46	115.43	(-)67.97	1173.22	856.53	316.69
भारत सरकार से ऋण	81.87	78.86	3.01	67.97	85.09	(-)17.12	50.23	17.59	32.64	200.07	181.54	18.53
एन0सी0डी0 सी0	18.26	39.22	(-)20.96	28.30	17.24	11.06	-.	-	-	46.56	56.46	(-)9.90
अन्य ऋण	-	582.59	(-)582.59	-	582.08	(-)582.08	-	107.40	(-)107.40	-	1272.07	(-)1272.07
योग	5200.13	3099.68	2100.45	4932.03	3177.41	1754.62	1197.69	240.42	957.27	11329.85	6517.51	4812.34

तालिका-I

II. बजट को समझने के लिए मुख्य संकेतक।

(रुपए करोड़ों में)

		वास्तविक 2017-18	बजट अनुमान 2018-19	बजट अनुमान 2019-20
ग.	पूंजीगत प्राप्तियाँ			
	(i) सकल ऋण (excluding W&M/overdraft but includes net PF receipts)	6592.12	7730.20	8330.75
	(ii) ऋणों की वसूलियाँ	39.61	34.55	26.73
	(iii) पूंजीगत विविध प्राप्तियाँ	34.82	0.00	0.00
	योग (पूंजीगत प्राप्तियाँ)	6666.55	7764.75	8357.48

मुख्यमन्त्री के ब्यान और इन आंकड़ों के बाद यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या मुख्यमन्त्री सही में सदन से कुछ छुपा रहे हैं या अफसरशाही ने जानबूझ कर मुख्यमन्त्री को इन आंकड़ों को नज़रअन्दाज़ करके कुछ और ही तस्वीर उनको दिखा दी है। मुख्यमन्त्री ने सदन में माना है कि प्रदेश की वित्तिय स्थिति ठीक नही है और इसके लिये उन्होंने कांग्रेस के पिछले कार्यालय में 18000 करोड़ से कुछ अधिक का ऋण लेने को जिम्मेदार ठहराया है।

लेकिन यह जिम्मेदार ठहराने के बाद यह सरकार राजस्व बढ़ाने के लिये क्या कदम उठा रही है इसका कोई खुलासा अभी तक सामने नही आया है। बल्कि सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि क्या कर्ज की ही सही स्थिति को सरकार समझ पायी है या नही। क्योंकि बजट में जो पूंजीगत प्राप्तियां दिखायी जाती हैं वह वास्तव में कर्ज ही होती हैं और बजट दस्तावेजों में उसे पूरी स्पष्टता के साथ कर्ज ही दिखाया गया होता है। परन्तु जब कर्ज पर सदन में सवाल पूछा जाता है और उसका उत्तर दिया जाता है तो इस ऋण का कोई जिक्र ही नही उठाया जाता है। क्योंकि यह ऋण अधिकांश में उस पैसे में से लिया जाता है जो आम आदमी की स्माल सेविंग और कर्मचारियों की भविष्य निधि या और किसी तरीके से सरकार के पास जमा होता है लेकिन सरकार उसकी मालिक नही होती। यह कर्ज वापिस किया जाता है। 2018 -19 में 7730.20 करोड़ और 2019-20 में 8330.75 करोड़ का ऐसा ऋण लिया जायेगा। बाजार और अन्य ऐजैन्सीयों से लिया जा रहा है ऋण इस कर्ज से अलग होता है। पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में लिया जाने वाला ऋण सिद्धान्त रूप में भविष्य के लिये संसाधन खड़े करने के लिये लिया जाता है जिनसे आगे आने वाले समय में सरकारी कोष में निश्चित और नियमित आय हो सके। आज प्रदेश में कर्जभार 50,000 करोड़ से पार हो गया है लेकिन इस कर्ज से कौन से संसाधन खड़े किये गये और उनसे कितनी आय हो रही है इसको लेकर आजतक कोई खुलासा जनता के सामने नही रखा गया है। इस परिदृश्य में यदि प्रदेश की पूरी वित्तिय स्थिति का सरकारी दस्तावेजों के आईने में ही आकलन किया जाये तो कोई भी सरकार जनता के सामने सही स्थिति नही रख रही है।

सहायक दवा नियंत्रक सरीन प्रकरण में सरकार की नीयत पर उठे सवाल

शिमला/शैल। स्वास्थ्य विभाग ने बद्दी में तैनात सहायक दवा नियंत्रक निशांत सरीन के आवास -कार्यालय और अन्य ठिकानों पर 23 अगस्त को विजिलैन्स ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान कई संपत्तियों बैंक खातों और फार्मा कंपनीयों के पैसों से मंहगे होटलों में ठहरने तथा हवाई यात्राएं करने के सबूत मिलने का दावा किया गया था। सरीन की एक सहयोगी डा. कोमल की पंचकूला स्थित फार्मा कंपनी पर भी इसी संबंध में छापेमारी की गयी थी। इस छापेमारी के दौरान सरीन और उनकी सहयोगी डा. कोमल विजिलैन्स टीम के साथ नही थे जिसका अर्थ है कि शायद उन्हें इस संभावित छापेमारी की भनक पहले ही लग गयी थी इसी कारण से वह इन ठिकानों पर हाथ नही लगे। इस छापेमारी के बाद विजिलैन्स ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके इन्हें सोलन कार्यालय में जांच में शामिल होने का नोटिस जारी कर दिया था।

लेकिन विजिलैन्स के नोटिस के बावजूद यह लोग जांच में शामिल नही हुए। बल्कि सोलन की अदालत मे अग्रिम जमानत के लिये याचिका दायर कर दी। इस याचिका के दौरान भी सरीन अदालत मे नही आये। यह याचिका भी खारिज हो गयी है। सरीन को जमानत नही मिली है। जमानत न मिलने के बावजूद भी विजिलैन्स ने उन्हें अभी तक गिरफ्तार नही किया है न ही सरीन अब तक जांच में शामिल हुए हैं। वह बद्दी में अपने कार्यालय में भी नही आ रहे हैं। माना जा रहा है कि वह भूमिगत हो गये हैं और जमानत के लिये प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रयास करेंगे। अग्रिम जमानत के लिये प्रयास करना उनका कानूनी अधिकार है लेकिन इस अधिकार से विजिलैन्स की कारवाई नही रूक जाती है। जब सरीन को सोलन की अदालत से जमानत नही मिली है तब कायदे से विजिलैन्स को उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर देने चाहिये थे। लेकिन ऐसा कुछ सामने नही आया है।

सरीन एक सरकारी कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है और विजिलैन्स छापेमारी कर चुकी है और वह उन्हें नही मिले हैं। वह अपने कार्यालय में भी नही आ रहे हैं क्या उन्होंने विभाग से कोई छुट्टी ले रखी है। यदि ऐसी कोई छुट्टी है तो क्या वह यह मामला दर्ज होने के बाद रद्द नहीं हो जानी चाहिये थी? यदि वह बिना किसी छुट्टी के अपने कार्यालय से गायब है तो क्या उसके खिलाफ एक और आपराधिक मामला नही बन जाता है? क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना सूचना के गायब नही रह सकता। लेकिन विभाग की ओर से इस तरह की कोई कारवाई अबतक अमल में नहीं लायी गयी है। स्मरणीय है कि बहुत पहले बिलासपुर में भी सरीन के खिलाफ ऐसा ही एक मामला बना था उस समय भी राजनीतिक दबाव होने की चर्चाएं उठी थी। अब भी माना जा रहा है कि शायद राजनीतिक दबाव फिर हावि हो गया है जिसने सरकार और विजिलैन्स दोनों के हाथ बांध रखे हैं।

राज्यपाल द्वारा विद्यार्थियों के शारीरिक व बौद्धिक विकास पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल

शिमला/शैल। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विद्यार्थियों के शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए योग की महता पर बल दिया है। उन्होंने लड़कियों में आत्म-सुरक्षा की भावना विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करने पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्व: अनुशासन की भावना पैदा करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

राज्यपाल, राजभवन में हिमाचल प्रदेश भारत स्काउट एण्ड गाइड के राज्य मुख्य आयुक्त व निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा तथा अन्य पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने राज्यपाल को भारत स्काउट एण्ड गाइड का स्कार्फ पहनाकर सम्मानित भी किया।

इस अवसर पर, कलराज मिश्र ने कहा कि स्काउट एण्ड गाइड युवाओं के संपूर्ण शारीरिक व बौद्धिक विकास में योगदान दे रहा है। यह विद्यार्थियों में छिपे गुणों को उभारने में मदद करता है तथा बहुआयामी कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति में सकारात्मक सोच विकसित करने में हिमाचल प्रदेश भारत स्काउट एण्ड गाइड को महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि एच पी बी एस जी इस बात पर विशेष ध्यान दे कि उनसे जुड़े विद्यार्थियों का कौशल विकास किस तरह हो सकता है और उनमें विकास की दृष्टि से क्या आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चों में आपदा प्रबंधन के प्रति भी जागरूकता व प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों में अनुशासन होना बहुत जरूरी है और यह कैसे स्थापित किया जाए, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में ही बच्चों को पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या करना जरूरी है और क्या नहीं, जिससे वह भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

सितंबर में आयोजित होगा पोषण माह, स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के विस्तार पर होगा ध्यान केन्द्रित

शिमला/शैल। सितंबर, 2019 का देश भर में पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान कुपोषण की चुनौतियों को दूर करने और समग्र पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पोषण अभियान के तहत जन आन्दोलन चलाया जाएगा। राज्य में इस माह के दौरान लोगों को पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करने और राज्य सरकार द्वारा बच्चों के लिए चलाई जा रही पोषण सेवाओं, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक पोषण के बारे में अवगत करवाने जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

यह बात अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता निशा सिंह ने पोषण माह की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि पोषण माह अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य और पोषण की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके लिए नवीन पहल 'पोषण भागीदारी' पर ध्यान केंद्रित होगा। पोषण संबंधी मुद्दों को ग्रामीण स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 'पोषण पर चर्चा' और व्यवहारिक परिवर्तन से निपटने के लिए 'पोषण चौपाल' की भी शुरूआत की जा रही है।

इस वर्ष के पोषण माह के दौरान पांच महत्वपूर्ण घटकों पर ध्यान केन्द्रित होगा, जिनमें बच्चे के पहले 1000 दिन, एनीमिया, दस्त, हाथ धोना और स्वच्छता तथा पौष्टिक आहार शामिल हैं।

निशा सिंह ने कहा कि पोषण माह छोटे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बीच पोषण को बढ़ावा देगा। महिला और बाल विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों और प्रवासी आबादी के बीच स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के विस्तार का प्रयास करने के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में जन आंदोलन गतिविधियों को बढ़ावा देगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हाल ही में पोषण अभियान के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीन पुरस्कार मिले हैं। अब राज्य इस संख्या को दस तक ले जाने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए विभाग अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ काम करेगा।

स्टाफ नर्स के पदों को भरने के लिए 5-6 सितंबर को होगी काउंसलिंग

शिमला/शैल। भूतपूर्व सैनिकों, सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और स्वतंत्रता सेनानियों के वार्ड के संबंध में स्टाफ नर्सों के रिक्त पदों को भरने के लिए काउंसलिंग 5 और 6 सितंबर, 2019 को आयोजित की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि काउंसलिंग परिमहल, शिमला में आयोजित की जाएगी और उम्मीदवारों को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिनमें रोजगार विनियम कार्ड, बायोडाटा परफोर्मा, जो कार्यालय की वैबसाइट www.hphealth. nic.in भूतपर्व सैनिक प्रमाण पत्र डिस्चार्ज बुक, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दसवीं, जमा दो, जीएनएम/बी.एस.सी. नर्सिंग, हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, हिमाचल प्रदेश नागरिकता प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो व अन्य सम्बन्धित दस्तावेज शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग के समय प्रस्तुत दस्तावेज मान्य होंगे व काउंसलिंग समाप्त होने के बाद किसी भी दस्तावेज को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The **Executive Engineer, Palampur Division, HPPWD, Palampur on behalf of Governor of Himachal Pradesh,** invites the item rate bids, in electronic tendering system from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the works as detailed in the table:-

Sr..No. Name of Work	Estimated cost	Starting Date for downloading Bid	Earnest Money	Deadline for submi-ssion of bid
1. Annual surfacing of Dharamshala Yol Dadh Palampur road in KM. 15/000 to 33/000 (SW:- Providing & Laying Bituminous Concrete at Km. 15/000 to 15/250)	5,08,620/-	4.09.2019	10200/-	17.09.2019
2. Annual surfacing of Dharamshala Yol Dadh Palampur road in KM. 15/000 to 33/000 (SW:- Providing & Laying Bituminous Concrete at Km. 15/250 to 15/500)	5,08,620/-	4.09.2019	10200/-	17.09.2019
3. Annual surfacing of Dharamshala Yol Dadh Palampur road in KM. 15/000 to 33/000 (SW:- Providing & Laying Bituminous Concrete at Km. 15/500 to 15/750)	5,08,620/-	4.09.2019	10200/-	17.09.2019
4. Annual surfacing of Dharamshala Yol Dadh Palampur road in KM. 15/000 to 33/000 (SW:- Providing & Laying Bituminous Concrete at Km. 15/750 to 16/000)	5,08,620/-	4.09.2019	10200/-	17.09.2019
5. Annual surfacing of Dharamshala Yol Dadh Palampur road in KM. 15/000 to 33/000 (SW:- Providing & Laying Bituminous Concrete at Km. 25/000 to 25/400)	6,22,311/-	4.09.2019	12,500/-	17.09.2019
6. Annual surfacing of Dharamshala Yol Dadh Palampur road in KM. 15/000 to 33/000 (SW:- Providing & Laying Bituminous Concrete at Km. 25/400 to 25/800)	6,22,311/-	4.09.2019	12,500/-	17.09.2019
7. Annual surfacing of Dharamshala Yol Dadh Palampur road in KM. 15/000 to 33/000 (SW:- Providing & Laying Bituminous Concrete at Km. 25/800 to 26/200)	6,22,311/-	4.09.2019	12,500/-	17.09.2019
8. Annual surfacing of Dharamshala Yol Dadh Palampur road in KM. 15/000 to 33/000 (SW:- Providing & Laying Bituminous Concrete at Km. 26/200 to 26/600)	6,22,311/-	4.09.2019	12,500/-	17.09.2019
9. Annual surfacing of Dharamshala Yol Dadh Palampur road in KM. 15/000 to 33/000 (SW:- Providing & Laying Bituminous Concrete at Km. 26/600 to 27/000)	6,22,311/-	4.09.2019	12,500/-	17.09.2019
10. Annual surfacing of Dharamshala Yol Dadh Palampur road in KM. 15/000 to 33/000 (SW:- Providing & Laying Bituminous Concrete at Km. 27/000 to 27/400)	6,22,311/-	4.09.2019	12,500/-	17.09.2019
11. Annual surfacing of Dharamshala Yol Dadh Palampur road in KM. 15/000 to 33/000 (SW:- Providing & Laying Bituminous Concrete at Km. 27/400 to 27/800)	6,22,311/-	4.09.2019	12,500/-	17.09.2019

The bidders are advised to note other details of tenders from the department website **WWW.hptenders.gov.in**

Adv. No.-1717/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

महिला एवं बाल विकास निदेशालय को स्कॉच ऑर्डर-ऑफ-मेरिट अवार्ड

शिमला/शैल। राज्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निदेशालय को बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले अनाथ एवं परित्यक्य बच्चों के कौशल विकास एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्कॉच ऑर्डर-ऑफ-मेरिट अवार्ड- 2019 प्रदान किया गया है।

विभाग को इस अवसर पर स्कॉच अवार्ड फॉर गवर्नेंस (कांस्य) के अवार्ड से भी नवाजा गया।

नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान नीति आयोग के सदस्य ने ये अवार्ड प्रदान किए। हिमाचल प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त निदेशक रविन्द्र सिंह गुलेरिया ने विभाग की ओर से यह अवार्ड प्राप्त किया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने विभाग की पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला एवं बाल विकास के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है जिसके लिए सरकार विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित कर रही है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निशा सिंह और निदेशक महिला एवं बाल विकास कृतिका कुलेहरी ने विभाग की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों के कौशल विकास व उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करवाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा।

केन्द्र ने हिमाचल को कैम्पा के अंतर्गत 1660 करोड़ रुपये जारी

शिमला/शैल। वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार ने कैम्पा के तहत राज्य के लिए 1660 करोड़ रुपये की लम्बित धनराशि जारी कर दी है। इस राशि को प्रदेश में विभिन्न वानिकी गतिविधियों में व्यय किया जाएगा।

उन्होंने इस धनराशि को जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि प्रदेश में हरित आवरण में वृद्धि और लोगों को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध करवाने में लाभकारी सिद्ध होगी।

इससे पूर्व, नई दिल्ली में केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में आयोजित वन मंत्रियों के सम्मेलन में गोविन्द सिंह ठाकुर ने कैम्पा और वन विभाग से सम्बन्धित प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों को उठाया।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश को फॉरेस्ट क्लीयरेंस एक्ट, 1980 के तहत विकास परियोजनाओं को त्वरित स्वीकृतियां प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश को क्षेत्रीय वन कार्यालय देहरादून के बजाय केन्द्रीय वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत लाने का आग्रह किया।

वन मंत्री ने विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए एफसीए, 1980 के अंतर्गत प्रदेश सरकार को एक हेक्टेयर के स्थान पर पांच हेक्टेयर सीमा तक विकास परियोजनाओं के लिए वन मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इको-टूरिज्म कि क्रियान्वयन के लिए इसे वानिकी गतिविधियां मानकर मापदंड निर्धारित करने चाहिए।

उन्होंने सम्मेलन के दौरान कैम्पा से संबंधित विभिन्न मुद्दों को भी उठाया और सीएएफ अधिनियम-2016 और सीएएफ नियम-2018 के तहत परिकल्पित राष्ट्रीय प्राधिकरण से निधि के हस्तांतरण की मांग की।

गोविंद सिंह ठाकुर ने राज्य कैम्पा निधि के तहत पैसा खर्च करने के लिए लेखांकन प्रक्रिया के सरलीकरण और ट्रेजरी मोड के स्थान पर पुरानी प्रणाली बहाल करने का आग्रह किया। उन्होंने वन अपराधों और आग की घटनाओं को रोकने के लिए फील्ड अधिकारियों को किराए पर वाहन इस्तेमाल करने प्रावधान करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि नियमों में बुनियादी ढांचे के विकास के तहत फंट लाइन कर्मचारियों के कार्यालय/आवासीय भवनों के रख-रखाव के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा कि प्रथम सितम्बर से 15 अक्तूबर, 2019 तक राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनएसवीपी) के माध्यम से मतदाता सत्यापन कार्यक्रम चलाया जाएगा।

उन्होंने इस अवसर पर मतदाताओं के अधिकारों और दावों को दर्शाने वाले पोस्टर को जारी कर मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) का शुभारम्भ किया।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की विसंगतियों को दूर करने के लिए मतदाता सत्यापन कार्यक्रम को आरम्भ किया है।

उन्होंने कहा कि शीघ्र बूथ स्तर की मोबाइल ऐप को आरम्भ किया जाएगा, जिसके माध्यम से बूथ स्तर के अधिकारी नाम, पता, फोटो जैसी जानकारियों को दर्ज कर सकेंगे। जिससे मतदाता सूचियों को पूर्ण रूप से शुद्ध करने में सहायता प्राप्त होगी।

देवेश कुमार ने कहा कि मतदाता वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकमित्र केन्द्र, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय (एसडीएम) और पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग मतदाता) हेल्पलाइन आदि के माध्यम से प्रत्येक मतदाता अपनी संबंधित मतदाता सूची में विद्यमान प्रविष्टियों का सत्यापन कर सकता है।

दलाश में राजकीय बहु–तकनीकी संस्थान खोलने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जिला कुल्लू के आनी क्षेत्र के दलाश में राजकीय बहु-तकनीकी संस्थान खोलने का निर्णय

लिया गया। इस संस्थान के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 97 पद सृजित कर भरे जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने जिला ऊना के बंगाणा में युवाओं की सुविधा के लिए उप-रोजगार कार्यालय खोलने का निर्णय लिया। इसके संचालन के लिए चार पदों को सृजित कर भरा जाएगा।

बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भुंतर को तेगुबहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विलय कर 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इस अस्पताल के लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को सृजित किया जाएगा।

मन्त्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी तथा रेडियोलॉजी विभागों में एक-एक सहायक प्रोफेसर के पदों को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का निर्णय लिया।

मन्त्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यक्रम अधिकारियों के 27 और चिकित्सा अधिकारियों के दो पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति दी।

बैठक में भरमौर, पांगी तथा लाहौल जनजातीय क्षेत्रों में नये खोले गए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर 50 शैक्षणिक तथा गैर -शैक्षणिक पदों को सृजित करने तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर के लिए रामपुर तथा सिरमौर के लिए नाहन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरणों में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर आशुटंककों के चार पद तथा दैनिक आधार पर सेवादार के चार पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मन्त्रिमण्डल ने जिला मण्डी के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल नेरचौक के परिसर में बागी उपमण्डल के तहत विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित करने तथा भरने सहित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया अनुभाग खोलने का भी निर्णय लिया।

बैठक में नगर एवं ग्राम योजना विभाग में अनुबंध आधार पर योजना अधिकारी के दो रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मन्त्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की। बी.के.अग्रवाल को भारत सरकार में सचिव लोकपाल नियुक्त किया गया है।

केन्द्र सरकार ने एनडीआरएफ के तहत जारी की 64.49 करोड़ राशि

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत जारी की गई 64.49 करोड़ की राशि जारी करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। यह राशि गत सर्दियों के मौसम के दौरान हुए नुकसान की भरपाई व अन्य सहायता कार्यो के लिए जारी की गई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह दूसरा अवसर है कि प्रदेश सरकार द्वारा सर्दियों में हुए नुकसान के लिए इस प्रकार की राशि प्राप्त की गई है। इससे पूर्व प्रदेश सरकार ने 2014 में एन.डी. आर.एफ. के अन्तर्गत सहायता राशि प्राप्त की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाहौल-स्पीति जिला में भारी बर्फबारी के कारण फंसे हुए स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों को निकालने के लिए राज्य सरकार के आग्रह पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को हैलीकाप्टर की सेवाएं तथा अन्य मदद प्रदान की गई थीं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि 2018 में मानसून के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने इस कोष के अन्तर्गत 312 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार प्रदेश की जनता के कल्याण के प्रति संवेदनशील है। जय राम ठाकुर ने कहा कि इस मानसून के दौरान भी प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 15 करोड़ रूपये की राशि राहत एवं बचाव कार्यो के लिए जारी की गई है ताकि प्रदेश की जनता को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केन्द्रीय टीम को राज्य में भेजने का आग्रह करेगी ताकि शीघ्र केन्द्रीय सहायता प्राप्त की जा सके।

मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग आवश्यकः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग, जॉगिंग के अतिरिक्त ब्रिस्क वॉकिंग आदि गतिविधियों के लिए रोजाना कम से कम एक घंटे

का समय निकालना आवश्यक है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विधानसभा परिसर में 'फिट इंडिया अभियान' के आयोजन के अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस, 2019 के अवसर पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी परिसर से राष्ट्र के लिए 'फिट इंडिया अभियान' का शुभारम्भ किया। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रसिद्ध मेजर ध्यान चंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त, 1905 को हुआ था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई देशों में शारीरिक गतिविधियों को सांस्कृतिक गतिविधियों के रुप में अपनाया गया है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से स्वस्थ रहने की अपील की तथा कहा कि कुछ दशकों पहले स्वस्थता हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग था, एक सामान्य व्यक्ति दिन में कम से कम 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलता था। उन्होंने कहा कि इस सम्पूर्ण कार्यक्रम की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई है तथा उन्होंने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं।

विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री परिषद, विधायक और विभिन्न निगमों व बोर्डो के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी परिसर से प्रधानमंत्री के 'फिट इंडिया अभियान' के शुभारम्भ को लाईव देख रहे थे।

फिट इंडिया अभियान के शुभारम्भ के अवसर पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन) मनोज तोमर, निदेशक एवं विशेष सचिव (राजस्व व आपदा प्रबन्धन) दुनी चंद राणा और निदेशक सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक उद्यमी एवं विशेष सचिव (वित्त) राजेश शर्मा सहित सचिवालय के कर्मचारी भी इसमें शामिल हुए। प्रदेश के सभी जिलों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

HRTC सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी

शिमला/शैल। वन, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मन्त्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 6 प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस वृद्धि के साथ अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों का महंगाई राहत भत्ता 134 प्रतिशत से बढ़कर 140 प्रतिशत हो गया है।

उन्होंने कहा कि इसके निर्णय से एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के साथ किया गया वायदा भी पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के सत्ता के आने से पूर्व यह महंगाई भत्ता 113 प्रतिशत पर स्थिर था तथा सरकार ने इस पर गम्भीर चिन्तन करने के उपरान्त यह राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है।

गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि 1 जनवरी, 2017 से लेकर 31 मार्च, 2017 तक सेवानिवृत्त हुए सभी 145 कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी के भुगतान हेतु 8.40 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह राशि 15 सितम्बर, 2019 तक प्रदान कर दी जाएगी। इससे पूर्व भी सरकार द्वारा 31 दिसम्बर, 2016 तक सेवानिवृत्त हुए 313 कर्मचारियों के बकाया 11.94 करोड़ रूपये का भुगतान अगस्त, 2019 में किया गया था। उन्होंने कहा कि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के खिलाडियों का डाइट भत्ता भी 120 रूपये से बढ़ाकर 250 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है, वहीं प्रदेश से बाहर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी 200 रूपये से बढ़ाकर 400 रूपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह डाइट भत्ता पिछले सात वर्षो से नहीं बढ़ाया गया था।

हिमाचल सरकार शिमला, मनाली और धर्मशाला में रोप–वे के माध्यम से परिवहन सुविधा प्रदान करेगी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे शहरों क्षेत्रों में भीड़-भाड़ कम करने, ग्रामीण बस्तियों को जोड़ने, पर्यटकों के आकर्षण के नए स्थानों को सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से रोप-वे के माध्यम से अभिनव परिवहन सुविधा प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता कर रही है। इसके साथ ही रोप-वे के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन क्षमता में वृद्धि लाने, सभी मौसमों में जनजातीय क्षेत्रों के लिए आवाजाही सुनिश्चित बनाने और उच्च घनत्व वाली सड़कों में ओवरहेड परिवहन सुविधा प्रदान करने पर भी बल दिया जा रहा है। रोप-वे परियोजनाओं में त्वरित निष्पादन पर बल देने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश एरियल रोप-वे अधिनियम, 1968 पर विधानसभा में संशोधन किया है, जिसे 29 अगस्त, 2019 को पारित किया गया है। भवन की छत के ऊपर से वर्टिकल निकासी की वर्तमान धारा (टीसीपी कानून के तहत अधिकतम इमारत की ऊंचाई निर्धारित है) और कैबिन के आधार को भारतीय मानकों के अनुसार अधिकतम 10 से 5 मीटर तक बदल दिया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) विभिन्न मामलों में 1.5 मीटर से 5 मीटर वर्टिकल निकासी की सलाह देता है।

वर्टिकल निकासी में इस बदलाव से रोप-वे परियोजनाएं तकनीकी -व्यावसायिक व्यवहार्य बनेंगी क्योंकि राज्य भूकम्पीय क्षेत्र-पांच में स्थित है जिससे इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अधिक संख्या में रोप-वे की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, टावरों की कम ऊंचाई के साथ भूमि, पेड़ो और पहाड़ियों को काटने की आवश्यकता काफी कम हो जाएगी। इससे इस पर्वतीय राज्य की नाजुक पारिस्थितिकी को बचाया जा सकेगा और कुल परियोजना लागत में भी काफी कमी आएगी। पीपीपी और अन्य सरकारी वित्त पोषित रो-वे के त्वरित निष्पादन के लिए समय और हिमाचल प्रदेश एरियल रोप-वे अधिनियम और अन्य खण्डों को रोप-वे के विस्तार के लिए सरल बनाया गया है। यह संशोधन इस क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने में सहायता करेगा व इससे पहले से रुकी हुई नई परियोजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

यह अधिनियम राज्य सरकार की दृष्टि में जनता के कल्याण के लिए कुशल परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए परिवहन क्षेत्रों में नवीनतम और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की दिशा में एक और सकारात्मक कदम है।

पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा 08 सितम्बर को केलंग में

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में जिला लाहौल स्पिति के लिए पुरुष व महिला वर्ग की भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परिक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 08 सितम्बर 2019 रविवार को 12 बजे से 01 बजे की बीच मे वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला केलंग मे आयोजित की जाऐगी। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पिति राजेश धर्माणी ने दी। उन्होंनें बताया कि लिखित परीक्षा के लिये उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्रातः 09 बजे परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करनी होगी। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में दिये जाऐगे। उम्मीदवारों को अपने साथ अपना एक रंगीन फोटो, पहचान पत्र जिसमे आधार कार्ड, डाईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि शामिल हैं लाना अनिवार्य होगा साथ ही कार्ड वोर्ड व नीला या काला बोलपेन भी साथ लाना होगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परीक्षा केंद्र मे उम्मीदवारों को हाफ स्लीप के हल्के कपडे तथा लो हिल की सेंडल व स्लीपर मान्य होगें। हाई हिल के जूते मान्य नही होगें। परीक्षा केंद्र में पर्स, चशमा, जमेटरी बॉक्स, पेंसिल, टोपी, घडी, गेहने, क्लकूलेटर, टैन डाईव, हैन्ड वैग व अन्य किसी भी प्रकार के इलैक्ट्रोनिक गैजेटस ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

लिखित परीक्षा 80 अंकों की होगी तथा इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगें। परीक्षा का स्तर 10+2 के समकक्ष होगी। इसमें अंग्रेजी, हिन्दी, सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान तथा रीजनिंग एप्टीचियूड के प्रश्न शामिल होंगे। उन्होनें अभ्यार्थियों से अनुरोध किया किसी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष न. 01900-202269 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते है।

मुर्ख लोगो से वाद – विवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते है.....चाणक्य

सम्पादकीय

नोटबंदी से आर बी आई तक

मोदी सरकार ने आरबीआई से 1.76 लाख करोड़ उसके सुरक्षित कोष से ले लिया है। यह पैसा लेने पर सरकार की आर्थिक नीतियों पर पहली बार एक बहस उठ खड़ी हुई है क्योंकि ऐसा शायद पहली बार हुआ है। कुछ लोग इसे सरकार का अधिकार मान रहे हैं। उनका तर्क है कि यह पैसा आर बी आई के पास सरप्लस पड़ा था जो सरकार के पास आकर सीधे निवेश में चला जायेगा। कुछ का मानना है कि यह एक गलत आचरण है और इससे आने वाले दिनों में इस सैन्ट्रल बैंक की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने शुरू हो जायेंगे। इस आशंका का आधार शायद बैंको का लगातार बढ़ता एनपीए है जिसे सख्ती से वसूलने के उपाय करने की बजाये उन्हें इस तरह से धन उपलब्ध करवा करके और छूट दी जा रही है। यह आशंका निराधार नही हैं क्योंकि बैंक आम आदमी के जमा पर दिये जाने वाले ब्याज में कटौती करके उसका लाभ कर्जदार की ब्याज दर कम करके उसको दे रहे हैं और इस कर्ज को वापिस लेना सुनिश्चित नही हो रहा है।

मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और वित्तमन्त्री के प्रबन्धन के सबसे पहले विरोधी बाजपेयी सरकार में रहे वित्तमन्त्री यशवन्त सिन्हा और उस समय विनिवेश मंत्री रहे अरूण शौरी तथा जाने माने अर्थशास्त्रीय राज्य सभा सांसद डा.स्वामी रहे हैं। ऐसे में यह समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि ऐसी स्थिति उभरी ही क्यों? इसके लिये 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के दौरान जो कुछ घटा है उस पर भी नज़र दौड़ाना आवश्यक हो जाता है। उस समय राजनाथ सिंह भाजपा के अध्यक्ष थे। उन्होने चुनावों के लिये एक स्ट्रैटजिक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी का अध्यक्ष डा.स्वामी को बनाया गया था और इसमें रा, सैन्य गुप्तचर तथा आई बी के पूर्व अधिकारी थे। इस कमेटी ने अपने अध्ययन के बाद कालेधन को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया था। जाली नोटों और आतंकवाद के लिये कालेधन को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। इन समस्याओं का एक मात्र कारगर हल नोटबन्दी माना गया था। इसलिये यह दावा किया गया था कि नोटबंदी से कालाधन, जाली नोट और आतंकवाद सब कुछ समाप्त हो जायेगा।

कमेटी की इस धारणा को जुलाई 2016 में आर बी आई की साईट पर आये मनी स्टॉक के आंकड़ों से बल मिल गया। इन आंकड़ों के अनुसार उस समय 17,36,177 करोड़ की करंसी परिचालन में थी। इसमें 475034 करोड़ तो बैंकों की तिजोरीयों में था और 16,61,143 करोड़ जनता के पास थी। जनता के पास 86% करंसी थी लेकिन यह बैंकों के पास आ नही रही थी। सरकार को मार्च 2019 तक ब्रेसल – 3 के मानक पूरे करने थे जिसे पूरा करने के लिये पांच लाख करोड़ चाहिये थे। इस आंकड़ों से यह धारणा और पुख्ता हो गयी कि देश में कालाधन सही में है और इसी कारण से यह बैंकों में वापिस नही आ रहा है। ऐसे में यदि नोटबन्दी करके जनता के पास पड़ी 86% करंसी को चलन से बाहर कर दिया जाये तो सरकार नये सिरे से नयी करंसी छाप सकती है और इसी से नोटबंदी का फैसला ले लिया गया। लेकिन आगे चलकर इस 86% करंसी की 99% से भी अधिक की करंसी वापिस आ गयी। इस 99% पुरानी करंसी को नयी करंसी के साथ बदलना पड़ा। परन्तु यह पैसा जनता का था और जनता का ही रहा। इसे नयी करंसी के साथ जब बदल दिया गया तो यह एकदम सफेद धन हो गया। इसी कारण से आर.बी.आई.और सरकार आज तक यह आकंड़ा जारी नही कर पाये हैं कि देश में कालाधन और जाली नोट कितने थे। इससे उल्टा सरकार पर यह आरोप आ गया कि नोटबन्दी के माध्यम से कालेधन और जाली नोटों को सफेद में बदलने का मौका दे दिया गया।

इस नोटबंदी से एन पी ए की समस्या अपनी जगह यथास्थिति बनी रही। यह एन पी ए सबसे अधिक उन घरानों का था जिन्होंने चुनावों में खुलकर धन साधनों को योगदान दिया था इसीलिये आगे चलकर सरकार को इन घरानों का 8.5 लाख करोड़ राईट ऑफ करना पड़ा। यह आकंड़ा संसद में आप सांसद सजंय सिंह ने रखा है जिसका सरकार कोई जवाब नही दे पायी है। इस तरह जब सरकारी खजाने को एन पी ए के नाम पर एक ही झटके में इतनी बड़ी चोट पहुंचा दी जायेगी तो इसका असर पूरी व्यवस्था पर पड़ेगा। इसी एन पी ए के कारण बैंक घाटे में चल रहे हैं बैंको के पास पैसा नही है। सरकार की योजनाओं को पूरा करने के लिये बैंकों को धन उपलब्ध करवाना आवश्यक है लेकिन जब कर्ज को वसूले बिना बैंकों को पैसा दिया जायेगा तो निश्चित और स्वभाविक है कि आर बी आई से उसका रिजर्व ही लिया जायेगा जिसकी शुरूआत अब हो गयी है। यह रिजर्व लेना रूकेगा या नही यह कहना कठिन है। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गर्वनर विरल आचार्य और गवर्नर उर्जित पटेल शायद इसीलिये छोड़ गये हैं क्योंकि वह इससे सहमत नही थे। आज आर बीआई से पैसा लेकर बैंको को रिफांईनैंस करके क्या उद्योगों में जो उत्पादन बन्द हो गया है और नौकरीयां चली गयी है क्या उसे पुन: बहाल किया जा सकेगा? क्या गरीब आदमी की बचत पर ब्याज कम करके उसका लाभ ऋणी को देना एक सही कदम है शायद नही। सरकार को लेकर यह धारणा बन गयी है कि उसकी प्राथमिकता तो बड़े उद्योग घरानों के हितों की रक्षा करना है और यह बात अब आम आदमी तक पहुंचनी शुरू हो गयी है। क्योंकि जिस ढंग से गरीब आदमी को बी पी एल से बाहर निकालने की योजनाएं बन रही है उससे गरीब आदमी सरकार पर ज्यादा देर तक विश्वास नही रख पायेगा। उसे मंदिर – मस्जिद और हिन्दु – मुस्लिम के द्धन्द में ज्यादा देर तक उलझा कर रखना कठिन होगा। आर बीआई से यह पैसा लेने के साथ यदि एन पी ए की वसूली के लिये सही में कड़े कदम न उठाये गये तो इस सबका कोई अर्थ नही रह जायेगा।

राज्य सरकार के प्रयासों से बागवानी विकास में स्थापित हुए नए आयाम

बागवानी राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। बागवानी विकास के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश में अपनी पहचान बनाई है। आज राज्य में 2.30 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी के अधीन है और फल उत्पादन भी बढ़कर अब 10.38 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

वर्तमान सरकार के नव प्रयासों के परिणामस्वरूप बागवानी विकास में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इस समय बागवानी का राज्य की वार्षिक आय में लगभग 3000 से 5000 करोड़ रुपये का योगदान हो गया है तथा औसतन 9 लाख लोग बागवानी गतिविधियों से आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान सरकार के दौरान लगभग 8446.93 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र बागवानी के अधीन लाया गया तथा प्रदेश में कुल 30.37 लाख पौधे बागवानों को वितरित किए गए।

इस दौरान एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत फल बागीचों के उच्चतम प्रबन्धन के लिए 3,049 शक्तिचालित उपकरण तथा 198 जल भण्डारण टैंक के लिए उपदान उपलब्ध करवाया गया। उद्यान आधारित पुनर्गठित फसल बीमा योजना को लागू किया है और इस योजना के अन्तर्गत 1,61,524 किसानों को कवर किया गया है तथा 70,104 बागवानों को 49.94 करोड़ रुपये की बीमा राशि का प्रभावित बागवानों को भुगतान किया गया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 18.89 करोड़ रुपये दिए गए है।

फल पौधों से अधिक व उत्तम गुणवत्ता की पैदावार प्राप्त करने के लिए उचित व संतुलित पोषक तत्वों के बारे परामर्श सेवा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष 20,000 पत्तियों के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। प्रदेश में बागवानी विकास के लिए 1134 करोड़ रूपये की सात वर्षीय विश्व बैंक पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना प्रारम्भ की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य चिन्हित बागवानी उत्पादों तथा फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं विपणन के लिए आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना, लघु किसानों व कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है।

इस परियोजना के अंतर्गत 90,734 बागवानों को व्यक्तिगत सम्पर्क, प्रशिक्षण शिविर, सेमिनार, प्रशिक्षण भ्रमणों का आयोजन करके

प्रशिक्षित किया गया। बागवानों को वितरण करने के लिए 25 लाख के 3,76,500 सम शीतोष्ण फल – पौधो (सेब व अखरोट) आयात किए गए और 9 लाख के 16,312 उपोष्णीय फल – पौधे (आम, लीची, अमरूद) अन्य राज्यों से मंगवाए गए। बागवानी की आधुनिक तकनीक में अब तक 58 विभागीय अधिकारियों को राज्य के बाहर प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड से आए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा 320 विभागीय अधिकारियों व 501 बागवानों को इस दौरान प्रशिक्षित किया गया।

फसलों, सब्जियों और फूलों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के दृष्टिगत 83,677 वर्गमीटर अतिरिक्त क्षेत्र को हरित गृह के अन्तर्गत और 9,44,215 वर्गमीटर ओला अवरोधक जालियों के अधीन लाया गया।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान फलदार पौधों में कीट – व्याधियों के नियन्त्रण के लिए 349.90 मीट्रिक टन पौध संरक्षण दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए 5.21 करोड़ रुपये का अनुदान फल उत्पादकों को दिया गया। फल उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करवाने के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब, आम तथा नीम्बू प्रजातीय फलों के लिए 371 प्रापण केन्द्र खोले गए हैं तथा बागवानों से 2064.74 लाख रुपये का 27,348.91 मीट्रिक टन फल खरीदा गया। बागवानों को वितरण के लिए 1,33,333 प्लास्टिक क्रेट की खरीद की गई ताकि बागवानों को विपणन की सुविधा सुलभ हो सके।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत औद्यानिकी विकास की परियोजनाओं के लिए कुल 3.50 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत बागवानी यंत्रीकरण के लिए राज्य में 196 यन्त्रचालित नैपसैक स्प्रेयर, 1500 हस्तचालित बागवानी यंत्र आवंटित किये गए हैं।

प्रतिकूल मौसम या प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से फल उत्पादकों को बचाने के लिए रबी मौसम 2017 – 18 में सेब, आम आड़ू, पलम और नीम्बू प्रजातीय फलों के लिए राज्य के 110 विकास खण्डों में मौसम

प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए उद्यान विभाग को आपदा राहत कोष के अन्तर्गत 2.7 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। प्रदेश के बागवानों को सामायिक तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए एम – किसान योजना प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत 7,68,774 किसानों का पंजीकरण किया गया है ताकि बागवान अपनी समस्याओं का तत्काल समाधान प्राप्त करके सफल फल उत्पादन कर सकें।

प्रदेश के उपोष्णीय क्षेत्रों में बागवानी विकास के लिए एशियन विकास बैंक की सहायता से 1688 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव किया गया है ताकि प्रदेश के शेष भागों में भी बागवानी गतिविधियां आरम्भ की जा सकें। सरकार के इन प्रयासों से भविष्य में इस प्रदेश को देश का अग्रणी फल उत्पादक राज्य बनाने में सहायता मिलेगी तथा बागवानों की आय में भी आशातीत वृद्धि सम्भव हो सकेगी।

दीन-दुखियों को सहारा देने में रेडक्रॉस सोसायटी की अहम भूमिका

दीन - दुखियों, गरीब तथा साधनहीन व्यक्तियों को सहारा देने में रेडक्रॉस सोसायटी अहम भूमिका अदा कर रही है। मानव सेवा में कार्यरत यह स्वयंसेवी संस्था न केवल राज्य एवं जिला स्तर तक बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी जरूरतमंद व्यक्तियों को अपनी सेवा प्रदान कर रही है। कुदरती आपदा हो या कोई दुर्घटना, किसी रोगी के लिए दवाइयों की जरूरत हो या खून की, रेडक्रॉस अपनी भूमिका अग्रणी रूप से अदा करती है।

कांगड़ा जिला में रेडक्रॉस मानवता के कष्ट को दूर करने, जरूरतमंदों की सहायता में बढ़ - चढ़कर अपना योगदान दे रही है। सोसायटी नए सदस्य बनाने एवं ज़मीनी स्तर पर लोगों को सोसायटी की गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में भी प्रभावी प्रयास कर रही है।

रेडक्रॉस सोसायटी कांगड़ा द्वारा निर्धन, बीमार, असहाय और अक्षम व्यक्तियों को उनके इलाज के लिए नि:शुल्क औषधियां, ऑपरेशन के लिए सहायता, निर्धन बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है तथा 01 अप्रैल, 2018 से अगस्त 2019 जक 513 व्यक्तियों की सहायता पर 17 लाख, 8 हजार 961 रूपये की धनराशि व्यय की गई है।

जिला में संस्था के माध्यम से एक पुनर्वास केन्द्र भी स्थापित किया गया है। इस केन्द्र में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को व्यायाम इत्यादि तथा आधुनिक उपकरणों से सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य के लिए केन्द्र में प्रशिक्षित फिजिशियन भी तैनात किए गए हैं, जो आधुनिक उपकरणों से विकलांग व्यक्तियों को व्यायाम इत्यादि के नियमित अभ्यास से उपचार में अपना योगदान देते हैं। यही नहीं प्रत्येक शनिवार को (दूसरे शनिवार को छोड़कर) क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में चिकित्सा बोर्ड द्वारा विकलांगता का आकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जिला के अन्य क्षेत्रों में भी विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए सोसायटी द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है तथा पात्र विकलांग व्यक्तियों को मौके पर ही सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं।

जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा अप्रैल, 2018 से अगस्त 2019 तक 112 कैंप दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए लगाए गए जिसमें 2334 व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया, जिसमें से 1538 को 40 प्रतिशत या उससे अधिक अक्षमता के मेडिकल प्रमाण - पत्र जारी किए गए हैं। सोसायटी द्वारा जिला कल्याण विभाग के सहयोग से 1538 दिव्यांग व्यक्तियों को बस पास तथा पेंशन सुविधा प्रदान करने के लिए रेफर किया गया। जिला पुनर्वास केन्द्र द्वारा सोसायटी के माध्यम से 101 व्यक्तियों को श्रवण यंत्र, 44 व्यक्तियों को व्हील चेयर, 05 को बैसाखियां तथा 07 व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, एक जोड़ी जूता, 06 व्यक्तियों को सीपी चेयर तथा 01 को ट्राई साईकल उपलब्ध करवाई गई है।

जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा प्रयास भवन में फिजियोथेरेपी यूनिट का संचालन किया गया है जिसमें सोसायटी द्वारा संचालित इस यूनिट में आधुनिक उपकरणों से विशेषज्ञों द्वारा मांसपेशियों के खिंचाव, जोड़ों के दर्द व अन्य हड्डियों के रोगों का उपचार किया जा रहा है तथा इन सुविधा से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सोसायटी ने अप्रैल, 2018 से अगस्त, 2019 तक 3710 रोगियों को यह सुविधा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त बीपीएल और 40 प्रतिशत से अधिक शारीरिक रूप से अक्षम 267 व्यक्तियों को नि:शुल्क फिजियोथेरेपी की सुविधा प्रदान की गई।

जिला रेडक्रॉस संस्था द्वारा चलाए जा रहे नशा निवारण केन्द्र धर्मशाला तथा नूरपुर में हजारों की संख्या में आए नशे की बुरी लत की गिरफ्त में फसें व्यक्तियों ने नशे के सेवन से निजात पाई है। धर्मशाला केन्द्र में नशे के चुगंल से छुटकारा पाने के लिए 01 अप्रैल, 2018 से अगस्त, 2019 तक 293 व्यक्तियों को जिनमें से 186 तो उपचार के लिए केन्द्र में भर्ती हुए हैं और 107 व्यक्तियों ने बाह्य रोगी तथा नूरपुर में 181 व्यक्तियों को जिनमें से 85 तो उपचार के लिए केन्द्र में भर्ती हुए हैं और 96 व्यक्तियों ने बाह्य रोगी के तौर पर उपचार प्राप्त किया और सभी नशा सेवन की लत से मुक्त हो कर गए है।

जिला रेडक्रॉस ने महिला सशक्तिकरण की ओर भी अपने कदम बढ़ाये हैं। रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा लड़कियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है, जहां छ: माह का प्रशिक्षण न्यूनतम शुल्क पर दिया जाता है। बीपीएल तथा 40 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षमता वाली लड़कियों व महिलाओं को यह सुविधा मुफ्त में प्रदान की जाती है।

उपायुक्त एवं रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष राकेश कुमार प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था द्वारा वस्त्र बैंक की स्थापना की गई है। जहां समर्थ एवं साधन सम्पन्न व्यक्ति अच्छे, साफ - सुथरे और प्रयोग योग्य वस्त्र जमा करवा सकते हैं ताकि विपत्ति में जरूरतमंद लोगों को वस्त्र उपलब्ध करवाए जा सकें।

रेडक्रॉस को सशक्त व समर्थ संस्था के रूप में उभारने के लिए साधन सम्पन्न एवं समर्थ लोगों के सहयोग की अपेक्षा रहती है। जिसके लिए जिला रेडक्रास सोसायटी समाज के सभी वर्गो से भरपूर योगदान के लिए प्रयासरत है। संस्था की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.redcrosskan gra.org पर भी प्राप्त की जा सकती है।

'ई-कॉमर्स' भारत में बदलता प्रतिस्पर्धा परिदृश्य

शिमला। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि ई - कॉमर्स में लोगों द्वारा डेटा के उपयोग के लिए एक सावधानीपूर्ण निरीक्षण की जरूरत है। इसे जब आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा जाता है तो यह विभिन्न मंचों को अप्रत्याशित बाजार शक्ति देता है। इसे उपभोक्ताओं के लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने यह बात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा 'ई - कॉमर्स' भारत में बदलता प्रतिस्पर्धा परिदृश्य' विषय पर आयोजित कार्यशाला के अवसर पर कही। इस परिदृश्य में सीसीआई और अन्य नियामकों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे इस चुनौती का सामना करने के लिए उद्योग के साथ मिलकर काम करें।

डॉ. राजीव कुमार ने साक्ष्य आधारित विनियमन को सक्षम बनाने के लिए अनुसंधान आधारित नीति निर्माण के लिए ई - मार्केट अध्ययन की जरूरत पर जोर देने के लिए सीसीआई को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत 9वीं सबसे बड़ी ई - कॉमर्स अर्थव्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की पहुंच से इसके दूसरे स्थान पर पहुंचने की संभावना है। उन्होंने ई - कॉमर्स की सुविधा के लिए नीति - निर्माताओं और नियामकों की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि यह खरीददारों, विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक है। उन्होंने कहा कि जीडीपी में बढ़ोतरी होने से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के सह - अस्तित्व के लिए पर्याप्त स्थान है। यह सुनिश्चित करने के लिए बाजार की शक्ति एकाधिकार की स्थिति में न पहुंचे सीसीआई को बड़ी भूमिका निभानी है।

इससे पहले सीसीआई के चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि बाजार सहभागियों तक सक्रिय रूप से पहुंच बनाने के लिए तथा किसी क्षेत्र को बेहतर रूप से जानने और अच्छे नीति - निर्माण पर आधारित सुधारों की पहचान करने के लिए बाजार अध्ययन की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ई - कॉमर्स के विकास से प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होने, सूचना पारदर्शिता लाने, उपभोक्ता की पसंद में भारी वृद्धि करने, बाजार म डलों में नवाचार को गति प्रदान करने तथा सहायता प्रदान करने की काफी संभावना है। लेकिन साथ - साथ ही यह अन्य बाजारों की तरह डिजिटल बाजार प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण के लिए अगम्य नहीं है। इसलिए प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों को ई - बाजार खुले और प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बड़ी भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल बाजारों की किस प्रकार देखरेख करनी चाहिए इसके लिए ऐसा अध्ययन किए जाने की जरूरत है कि ये पारिस्थितिकी तंत्र परम्परागत बाजार विन्यासों से किस प्रकार अलग हैं और प्रतिस्पर्धा विश्लेषण के क्या - क्या मानदंड होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अध्ययन और इस कार्यशाला का पूरा उद्देश्य परिचिर्चा काकम तात्विक और व्यवहारिक दृष्टि से अधिक संचालित करना है।

उद्घाटन सत्र के बाद विशिष्ट ई - कॉमर्स व्यापार जैसे ऑनलाइन भोजन डिलीवरी, ऑनलाइन होटल बुकिंग और ऑनलाइन खुदरा खरीददारी को समर्पित पैनल पर चर्चा हुई। इस पैनल में ई - कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के वरिष्ठ अधिकारियों, वाणिज्यिक क्षेत्र कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार, थिंक टैंक, संबंधित उद्योग और व्यापार संघों के प्रतिनिधि, आतिथ्य क्षेत्र के पेशेवरों, जाने - माने नौकरशाहों ने ई - कॉमर्स के सामने आ रही चुनौतियों और मुद्दों के बारे में व्यापक रूप से चर्चा की। चर्चा में ई - कॉमर्स बाजार स्थल और परम्परागत बाजारों के साथ इसके इंटरफेस दोनों में प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित और संरक्षित करने की जरूरत पर भी विचार - विमर्श किया गया। कार्यशाला नीति और विनियमन के मध्य सहभागी संबंध और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य पर इसके प्रभाव पर विचार - विमर्श के साथ समाप्त हुई। पसूका

इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम का शुभारंभ

शिमला। निर्वाचन आयोग ने मतदाता विवरणों को सत्यापित और प्रमाणित करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ किया। पूरे देश में 'इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम' के मेगा मिलियन लॉन्च के अवसर पर भारतीय निर्वाचन आयोग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में 1 सितम्बर, 2019 को एक विशेष कैम्प का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (https://www.nvsp.in) और मतदाता हेल्पलाईन एप का अनावरण करने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया का हृदय है।

आधारशिला मतदाता सूची है। मैं देश के सभी नगरिकों से आग्रह करता हूं कि वे सत्यापन कार्यक्रम में भाग लें, ताकि आयोग आने वाले सभी चुनावों के दौरान बेहतर मतदात सेवाएं प्रदान कर सके।

मतदाता सूची के बारे में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जब सभी मतदाता अपने ब्यौरों को सत्यापित और प्रमाणित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम की सफलता लोगों की भागीदारी पर निर्भर है। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और त्रुटिहीन मतदाता सूची सुनिश्चित करें, क्योंकि यह मतदान प्रक्रिया का हृदय है।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को बेहतर बनाना है, नागरिकों को बेहतर मतदात सेवाएं प्रदान करना है और आयोग तथा मतदाताओं के बीच संवाद को बेहतर बनाना है। 32 सीईओ ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, 700 डीईओ ने जिलों में और लगभग 10 लाख मतदान केंद्रों में बीएलओ/ईआरओ ने देश में सभी स्तरों पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम 1 सितंबर, 2019 से 15 अक्तूबर, 2019 तक चलेगा।

मतदाता एनवीएसपी पोर्टल (nvsp.in) या मतदाता हेल्प लाइन एप या साझा सेवा केंद्रों या निकट के किसी मतदान सुविधा केन्द्र पर जाकर निम्न सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

- ♦ वर्तमान विवरणों की जांच और सुधार
- ♦ निम्न दस्तावेजों के जरिए प्रविष्टियों का सत्यापन/प्रमाणन: (1) भारतीय पासपोर्ट (2) ड्राइविंग लाइसेंस (3) आधार कार्ड (4) राशन कार्ड (5) सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मियों का पहचान पत्र (6) बैंक खाता (7) किसान पहचान कार्ड (8) पेन कार्ड (9) आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड (10) पानी/बिजली/टेलिफोन/गैस कनेक्शन का नवीनतम बिल
- ♦ परिवार के सदस्यों का विवरण देना तथा उनकी प्रविष्टियों की जांच।
- ♦ मतदाता सूची में नाम वाले परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य जिनके नाम मतदाता सूची में हैं और जो स्थायी रूप से अन्य जगह जा चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है के विवरणों को अद्यतन करना।
- ♦ 1 जनवरी, 2001 को या इससे पहले जन्म लिए परिवार के योग्य सदस्यों तथा संभावित मतदाता, जिनका जन्म 2 जनवरी, 2002 से एक जनवरी, 2003 के बीच हुआ है और वे मतदाता के साथ रह रहे हैं के ब्यौरे को जमा करना।
- ♦ बेहतर मतदाता सेवाओं के लिए मोबाइल एप के माध्यम से आवास के जीआईएस को जोड़ना।
- ♦ वर्तमान के मतदान केंद्र के बारे में अनुभव साझा करना और यदि कोई अन्य वैकल्पिक मतदान केंद्र है तो इसकी जानकारी देना।

ब्यौरे के प्रमाणन से तथा मोबइल नंबर को साझा करने से मतदाताओं को ऑनलाइन आवेदन की स्थिति, ईपीआईसी की स्थिति, मतदान दिवस की घोषणाएं, मतदाता स्लिप आदि से संबंधित जानकारी उनके पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। मतदाता सूची की क्रमसंख्या में बदलाव, मतदान केंद्र का ब्यौरा बीएलओ /ईआरओ में बदलाव से संबंधित मतदान केंद्र की सभी जानकारी मतदाताओं के साथ साझा की जाएगी। इस अवसर पर निर्वाचन आयोग के कर्मियों ने अपने तथा अपने परिजनों के विवरणों का सत्यापन व प्रमाणन किया। पसूका

वर्ष 2024–25 तक प्राप्त कर लेंगे पांच ट्रीलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्यः अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केंद्रीय वित्त एवं कार्पोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैहरे (बड़सर) विश्राम गृह में लोगों से मुलाकात की और जन समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने इस अवसर पर विश्राम गृह परिसर में एक पौधा भी रोपित किया और पर्यावरण संरक्षण तथा हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इस बार उन्हें ऐतिहासिक बढ़त लोकसभा चुनावों में दिलाई है और इसका आभार व्यक्त करने वे यहां सभी के बीच पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बिलासपुर की जनसभा में उन्हें बड़ा आदमी बनाने की घोषणा की थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नई जिम्मेवारी सौंपी है जिसे बखूबी निभाने के लिए वे दिन-रात प्रयासरत रहेंगे। प्रधाानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रीलियन डॉलर की ऊंचाई तक ले जाने का लक्ष्य रखा है और उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2024-25 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि देश की इतनी बड़ी आबादी में से केवल सात करोड़ के लगभग करदाता हैं जो देश के विकास में अपना सतत योगदान दे रहे हैं। केंद्र सरकार करदाताओं का मान-सम्मान करेगी और पारदर्शी ढंग से कार्य करने वाले व्यापारी वर्ग को हर तरह से प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक समृद्धि की दिशा में भारत लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। बैंकिंग क्षेत्र में विलय सहित अन्य आर्थिक मोर्चों पर इसके लिए निरंतर ठोस कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बड़े व कड़े निर्णय लेनी वाली सरकार कार्य कर रही है जिसने आज देश को दुनिया की बड़ी ताकतों में ला खड़ा किया है। तीन तलाक की समाप्ति, जम्मू-कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 व 35 ए के असंगत प्रावधानों को खत्म करने के निर्णयों में यह साफ झलकता है।

दुनिया के अधिकांश देश इस निर्णय पर भारत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा है और छिटपुट मामलों को छोड़कर लोगों को आवाजाही के लिए छूट दी जा रही है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि पौधारोपण, जल संचयन तथा पॉलीथीन व प्लास्टिक मुक्त समाज आज समय की जरूरत है। उन्होंने उपस्थित लोगों का आहवान किया कि वे इन तीनों क्षेत्रों में स्वयं भी जागरूक बनें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। केंद्र सरकार ने अब सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व की भाजपा सरकार के समय से ही पॉलीथिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह कार्य करने वाला हिमाचल उस समय प्रथम राज्य बना।

उन्होंने कहा कि जल संचयन के लिए हमें ग्रामीण स्तर तक प्रयास करने की आवश्यकता है। पेयजल स्रोतों की नियमित साफ-सफाई रखें और इसका उपयोग केवल पानी पीने के लिए ही करें। उन्होंने कहा कि अगली बरसात से पूर्व सभी पंचायतों में जल संरक्षण का कार्य संपन्न करने का सभी आज से ही संकल्प लें। इसके लिए सांसद निधि सहित मनरेगा व 14वें वित्त आयोग से धन का प्रावधान किया जाएगा। इससे जहां भू-जल स्तर में वृद्धि होगी, वहीं खेतों तक सिंचाई योग्य पानी भी पहुंचाया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान में भी सभी लोग अपना सक्रिय योगदान दें। विशेष तौर पर पंचायतों में स्थापित कूड़ेदानों को नियमित तौर पर निस्तारित करने के लिए संबंधित पंचायतें जिम्मेवारी दिखाएं। उन्होंने कहा कि व्यर्थ पदार्थों से उत्पाद तैयार कर स्वयं सहायता समूह अपनी आर्थिकी मजबूत कर सकते हैं। इस दिशा में बेहतरीन कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों को देश की चुनिंदा कंपनियों से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार संयुक्त रूप से हिमाचल के विकास के लिए कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि हिमाचल से केंद्र को भेजी जाने वाली विकास परियोजनाओं को स्वीकृत करवाने में वे हर संभव सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय परियोजनाओं को धरातल पर तेजी से लागू करने में अधिकारी कार्यरत रहें। इसकी समीक्षा के लिए वे शीघ्र ही अधिकारियों के साथ एक बैठक भी आयोजित करेंगे।

LIC ने पूरे किये सेवा एंव विश्वास के 63 वर्ष

शिमला/शैल। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी स्थापना के 63 वर्ष पूरे कर दिये है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने पॉलिसी धारकों

की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिमला मण्डल के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 23 शारवाओं के अतिरिक्त 14 सैटैलाईट कार्यालय एक मिनि ऑफिस 294 प्रीमियम प्वाईट 28 प्लस केन्द्र स्थापित किये है।

शिमला मण्डल के वर्ष 2018-19 में 203251 पॉलिसी के अन्तर्गत 333.52 करोड़ प्रथम प्रीमियम आय अर्जित की। इस वित वर्ष से 31-8-2019 तक शिमला मण्डल ने लगभग 76486 पालिसी के अन्तर्गत 128.57 करोड़ की प्रथम प्रीमियम आय अर्जित की है। सूक्ष्म बीमा के क्षेत्र में शिमला मण्डल ने गत वर्ष 35590 पॉलिसी करके तथा 112 मधूर बीमा ग्राम बनाकर देश में प्रथम स्थान पाया है। जिसमें गैर सरकारी संगठन (NGO) मंडी साक्षरता एंव जन विकास समिति का विशेष योगदान रहा। चालू वित वर्ष में भी सूक्ष्म बीमा के क्षेत्र में मण्डल ने 31-8-2019 तक लगभग 18000 पॉलिसी करे के देश भर में प्रथम स्थान बनाये रखा।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने हिमाचल प्रदेश में 31-03-2019 तक कुल 10092.96 करोड़ का निवेश किया है जिसमें से 9830.29 करोड़ की राशि राज्य सरकार प्रतिभूतियों में 115.69 करोड़ अन्य सामाजिक क्षेत्र में निवेश 28.13 करोड़ राज्य के पेयजल योजनाओं में, 118.17 करोड़ कॉरपोरेट सैक्टर में कंपनी की शेयर डिबैंचर व लोन के लिये और 0.56 करोड़ सामाजिक आवास योजनाओं में निवेश किया है। शिमला मण्डल ने वर्ष 2018-19 में 252293 परिपक्वता दावों में 796.42 करोड़ का भुगतान किया जबकि 5747 मृत्यु दावों में 80.02 करोड़ का भुगतान किया है।

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 01-09-2019 से 07-09-2019 तक भारतीय जीवन बीमा निगम 'बीमा सप्ताह' के रूप में मना रहा है इस का शुभारंभ मण्डल प्रबन्धक द्वारा किया गया तथा नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करके विधिवत उद्घाटन किया। बीमा सप्ताह में विभिन्न शाखाओं में कई गतिविधियां की जायेंगी जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तदान शिविर, SOTY, अभिकर्ता दिवस, पौधारोपण, ग्राहक सम्मेलन शामिल हैं।

डॉ.श्रीकान्त बाल्दी ने संभाला मुख्य सचिव का पदभार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कैडर-1985 के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी डॉ. श्रीकान्त बाल्दी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया। डॉ. बाल्दी को प्रशासनिक कार्य का 34 वर्षों से अधिक का गहरा अनुभव है। अब तक के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदों कार्य किया है। उनके पास विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली विशेषकर वित्त मामलों की गहरी समझ है।

पदभार ग्रहण करने के उपरान्त डॉ. श्रीकान्त बाल्दी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को पारदर्शी प्रशासन देने के लिए कृतसंकल्प है और वह प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं, नीतियों व कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे।

मुख्य सचिव ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता नवम्बर माह में धर्मशाला में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट को सफल बनाना है। हालांकि विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी एक गम्भीर चुनौती बनी हुई है, इसके बावजूद हिमाचल सरकार ने इन्वेस्टर मीट आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसे सफलतापूर्वक आयोजित करने की दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएंगे ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित किया जा

सके जिससे प्रदेश की आर्थिकी मजबूत बनेगी और युवाओं रोज़गार के पर्याप्त अवसर मिल सकेंगे।

प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों, कर्मचारी संघों, जन प्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने पर डॉ. बाल्दी को उनके कार्यालय पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं दी।

नौकरी प्रदाता बनने की दिशा में कार्य करें छात्रः आईसीएआर एडीजी

शिमला/शैल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के शिक्षा योजना और गृह विज्ञान प्रभाग के सहायक महानिदेशक डॉ पीएस पांडे ने छात्रों को नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी प्रदाता बनने का आग्रह किया। डॉ पांडे डॉ वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान नए

छात्रों को संबोधित कर रहे थे। छात्रों को योगभारती, सोलन के समन्वयक योगचार्य श्रीनिवास मूर्ति के विचारों को सुनने का भी मौका मिला, जिन्होंने फिटनेस और भोजन की आदतों में सुधार के टिप्स दिए।

इस अवसर डॉ पांडे ने आईसीएआर की मान्यता प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में नौणी विवि द्वारा 12वां स्थान हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रशंसा की। डॉ पांडे ने कहा कि रैंकिंग के लिए गुणवत्ता संकाय महत्वपूर्ण है। उन्होंने सुझाव दिया कि पाठयक्रम को उद्योग की जरूरतों के अनुसार बनाया जाना चाहिए और छात्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहिए। डॉ पांडे ने एक सप्ताह की अवधि के ओरिएंटेशन कार्यक्रमों को डिजाइन करने का आहवान किया, जहां नए छात्रों को न केवल युवा उद्यमियों और उद्योग से जाने पहचाने नामों को सुनने और बातचीत करने का मौका मिले बल्कि उन्हें वृक्षारोपण जैसी सामाजिक गतिविधियों में भी जोड़ा जा सके। ईएलपी कार्यक्रम को कृषि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक बताते हुए डॉ पांडे ने छात्रों से आग्रह किया इस कार्यक्रम में छात्र सीखे और समाज की बेहतरी के लिए कार्य करे। उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को गुणवत्ता रोपण सामग्री पर अपने ईएलपी का विस्तार करने के प्रयास करने चाहिए।

समारोह के दौरान योगचार्य श्रीनिवास मूर्ति ने छात्रें को योग और स्वास्थ्य विषय पर संबोधित किया। उन्होंने कर्मचारियों और छात्रों को कई योग अभ्यास और स्वास्थ्य युक्तियाँ बताईं और उनसे सुखी और रोगमुक्त जीवन के लिए योग अपनाने का आग्रह किया।

सभा को संबोधित करते हुए, कुलपति डॉ परविंदर कौशल ने छात्रों को एक बेहतरीन शैक्षिक वातावरण प्रदान करने में विश्वविद्यालय का समर्थन करने के लिए आईसीएआर और डॉ पांडे को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह बहुत सौभाग्य की बात है कि शिक्षा योजना प्रभाग के एडीजी ने नए छात्रों को संबोधित करने के लिए नौणी विवि को चुना। डॉ कौशल ने विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय संस्थान बनाने के लिए बुनियादी ढांचे और शैक्षिक सुविधाओं में सुधार के लिए आईसीएआर के समर्थन की मांग की। इस मौके विश्वविद्यालय के अधिकारी, छात्र, और संकाय मौजूद रहे।

डॉ पीएस पांडे ने विश्वविद्यालय में नवनिर्मित 'नटराज बॉयज हॉस्टल' का उद्घाटन किया। इस चार मंजिला इमारत का निर्माण 2.5 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। 98 छात्र के इस हॉस्टल के निर्माण के लिए आईसीएआर द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की है। डॉ पांडे ने विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रयोगात्मक खेतों का भी दौरा किया और वैज्ञानिकों और छात्रों के काम की सराहना की।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

आऊटसोर्स बना कमीशन का सबसे बड़ा उद्योग

बिना निवेश के 94 लोगों को मिला 23 करोड़

शिमला/शैल। सरकार के सांख्यिकी विभाग के मुताबिक 31 मार्च 2018 को प्रदेश में पंजीकृत बेरोज़गार की संख्या 8,34,084 थी। 2017 में उद्योग विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के नीजि क्षेत्र में 1,58,000 लोगों को नौकरी प्राप्त थी। अब विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक रमेश धवाला के एक प्रश्न के उत्तर में आयी जानकारी के मुताबिक पिछले तीन वर्षो में 31-7-2019 तक प्रदेश के प्राईवेट सैक्टर में 1,41,494 लोगों को रोज़गार मिला है। इसके मुताबिक 2016-17 में 34842, 2017-18 में 40141, 2018-19 में 49345 और 2019-20 में 31-7-2019 तक 17166 लोगों को नौकरी मिली है। धवाला के अतिरिक्त विधायक होशियार सिंह, राजेन्द्र राणा, विक्रमादित्य सिंह ने रोज़गार को लेकर सवाल पूछा था कि सरकारी और प्राईवेट क्षेत्र में पिछले तीन वर्षो में कितने लोगों को रोज़गार मिला है। इनके जवाब में कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

विधायक मोहन लाल ब्राक्टा, मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य सिंह ने सवाल पूछा था कि सरकारी विभागों और उपक्रमों में आऊटसोर्स के माध्यम से कितने लोगों को नौकरी पर रखा गया है और क्या सरकार इनको नियमित करेगी या नही। इस प्रश्न के जवाब में कहा गया है कि प्रदेश में 12165 लोगों को आऊट सोर्स से नौकरी पर रखा गया है। इसमें यह भी जानकारी दी गयी है कि पिछले वर्ष लगभग 3000 कर्मचारी आऊटसोर्स पर रखे गये हैं। इन कर्मचारियों पर 153,19,80,030 (एक सौ तिरेपन करोड़ उन्नीस लाख अस्सी हजार तीस रूपये) खर्च हो रहे हैं और इसमें से 130,10,21,806 (एक सौ तीस करोड़ दस लाख इक्कीस हजार आठ सौ छः रूपये) कर्मचारियों को दिये जा रहे हैं और 23,09,58,224 (तेइस करोड़ नौ लाख अठावन हजार दो सौ चौबीस रूपये) इन्हें काम पर रखने वाली कंपनीयां अपना कमीशन रख रही है। यह कर्मचारी 94 कंपनीयों के माध्यम से रखे गये हैं।

यदि सरकार द्वारा सदन में रखे गये आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के निजि क्षेत्र में पिछले तीन वर्षो में 1,41,494 लोगों को नौकरी पर रखा गया है। पिछले तीन वर्षो में कितने उद्योग प्रदेश में आये हैं इसकी जानकारी भी धवाला के ही एक प्रश्न के उत्तर में दी गयी है उसके मुताबिक केवल 11 उद्योग आये हैं और यह भी अभी अनुमतियों की स्टेज पर हैं। अभी जो निवेश के लिये देश-विदेश में मीट किये गये हैं उन पर आये सवालों में एक जगह कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। दूसरी जगह कहा गया है कि एमओयू साईन नही हुआ है। स्वभाविक है कि नये प्रस्तावित निवेश में अभी तक किसी को नौकरी मिलने की कोई स्टेज नही हैं।

सांख्यिकी विभाग ने 2017-18 तक के जो आंकड़े जारी किये हैं उनमें 2005-06 से 2017-18 तक की स्थिति सामने रखी है। इसमें किस वर्ष कितने लोगों ने रोज़गार कार्यालयों में पंजीकरण करवाया कितने रिक्त स्थान नोटिफाई हुए। उनमें सरकार और प्राईवेट सैक्टर में कितने की प्लेसमैन्ट हुई यह सब दिया हुआ है। इसके मुताबिक 2005-06 से 2017-18 तक प्रदेश में सरकारी और प्राईवेट सैक्टर में एक लाख से भी कम लोगों को नौकरी मिली है। ऐसे में सवाल उठना स्वभाविक है कि सरकार द्वारा 2017 से 31-7-2019 तक प्राईवेट सैक्टर में 1,41,494 लोगों को रोज़गार मिलने के दावे के आंकड़ो की प्रमाणिकता पर कैसे विश्वास किया जा सकता है।

सरकार ने माना है कि आऊटसोर्स पर 12165 लोगों को नौकरी पर रखा गया है। यह लोग 94 कंपनीयों के माध्यम से रखे गये हैं और इन कंपनीयों को 23 करोड़ से अधिक का कमीशन दिया जा रहा है। स्मरणीय है कि आऊट सोर्स पर रखे गये कर्मचारियों ने वीरभद्र सरकार के दौरान उन्हें नियमित करने के लिये आन्दोलन किया था। इनके बारे में कोई स्थायी पॉलिसी लाने की बात की गयी थी। उस समय 30,000 से ज्यादा कर्मचारी आऊटसोर्स के आधार पर रखे होने के आंकड़े सामने आये थे। इन कर्मचारियों के आन्दोलन के बाद सरकार ने एक पॉलिसी जारी की थी उसमें इन्हें नियमित अवकाश आदि का लाभ दिया गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि भविष्य में कोई भी विभाग वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना आऊटसोर्स पर कोई भर्ती नही करेगा। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार बदलने के बाद पिछली सरकार के दौरान रखे गये कर्मचारियों को हटाकर उनके स्थान पर यह 12165 लोग नये सिरे से रखे गये हैं? क्या इनके लिये वित्त विभाग से पूर्व अनुमति ली गयी है। इन लोगों को कितने समय के लिये रखा गया है? यदि सरकार के पास इनके लिये काम नियमित रूप से है तो फिर इन्हें नियमित रूप से ही नौकरी पर क्यों नही रखा गया है क्या आऊटसोर्स कुछ लोगों को केवल कमीशन देने का एक माध्यम बनाया गया है। आऊटसोर्स के नाम पंजीकृत कंपनीयां जब कमीशन ले रही हैं तो क्या यह अपने कर्मचारियों को उसके बदले में कोई लाभ भी दे रही है।

गत 3 वर्षों में दिनांक 31.07.2019 तक सरकार ने 1,41,494 बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाया। वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	रोजगार
2016–17	34,842
2017–18	40,141
2018–19	49,345
01.04.2019 से 31.07.2019	17,166
कुल	**1,41,494**

XI- EMPLOYMENT [107

11.2- REGISTRATION & PLACEMENTS DONE BY THE EMPLOYMENT EXCHANGES

(Number)

Year	Candidates registered	Vacancies notified	Candidates placed	On live register at the end of the period
1	2	3	4	5
2005-06	1,69,623	4,674	4,763*	8,16,878
2006-07	1,49,012	6,132	6,127*	7,56,980
2007-08	1,46,519	4,358	4,697*	7,82,348
2008-09	1,67,437	7,287	7,381*	8,13,782
2009-10	1,30,480	4,235	4,080*	8,27,329
2010-11	1,20,042	6,732	4,368*	8,25,764
2011-12	1,35,781	10,573	11,620*	8,39,007
2012-13	1,68,779	5,611	11,309*	8,61,314
2013-14	2,77,903	5,777	8,485*	10,12,602
2014-15	1,77,309	4,381	9,089*	8,92,988
2015-16	1,99,892	3,486	7,347*	8,28,048
2016-17	1,77,441	5,624	5,243*	8,11,306
2017-18	2,06,664	8,462	5,297*	8,34,084

*Including Private Sector.
Source: - Directorate of Employment, Himachal Pradesh.

क्रम सं. आउटसोर्सिंग कम्पनियों का नाम एवं पता

1 National Institute of Electronic and Information Technology (NIELIT), Hotel Cedarwood, Jakhu Road-Shimla-171001.
2 MD Utility Service, Pathania Niwas, Sector -2, New Shimla
3 Saraswati Dot Com, Pvt. Ltd. Kasumpti, Shimla-9
4 M/s Manas Mantra Outsourcing Pvt. Ltd., Set. No. 3, Shanti Niwas, Nr Sanskrit College, Phagli, Shimla-4.
5 M/s HPESCO Security Service, MIIG-31, Housing Board Colony-Hamirpur (H.P.)
6 Sky light Manpower & Hospitality Services, Dera Parol Tehsil Bhoranj- Hamirpur (H.P.)
7 AP Securities Pvt. Ltd., 3rd Floor, Sharma Niwas, Opposite SBI Main Bazar Kasumpti Shimla-9
8 The Ma Tolotama Bhawan Nirman & Hydro Power Coop-Society C, VPO-Dualpur, Shastri Nagar, Kullu, H.P.
9 HP State Elect. Dev. Corp. Mehali, Shimla-03
10 M/s Shimla Cleanways, Sahibu Niwas, Sec-2, New Shimla-9
11 New Vision Commercial & Escort services, Ashirvaad Sadan, Mehli-Shimla
12 M/S RK & Co. Ukhali, Hamirpur.
13 HP Ex-Serviceman Corporation-Hamirpur-01
14 NRTC Sec-1, Parvanoo, Solan, HP
15 M/s New Eagle services, Kamla Bhawan, Kachi Ghati, Below Saytam Paradise Hotel, Kachi Ghati -Shimla, HP.
16 M/s Raj Kumar, Govt. Contractor, Vill-Ahen, PO Dhawal, Teh-Sundernagar-Mandi
17 National & Tech. Consortium (NRTC), Industries Campus, Sector-01, Parvanoo, Solan (H.P.)
18 National Tech. Research & Tech. Consortium-Parvanoo.
19 Vyas Infravyudalor Pvt. Ltd., Nr. Mahunag Temple, Tarna Hill Mandi.
20 M/s I L & FS Humana Resources, New Delhi
21 M/S Corporate Sector-II, New Shimla.
22 M/s B &V Consultancy Services, Near Labour Hostel, Lal Pani, Shimla.
23 M/s Sohan Lal Lalpani, Shimla.
24 M/S Rainbow Enterprises, Hemant Lounge, Mashobra-2, Shimla.
25 M/s Mebric Security M-31 Housing Board Colony-Hamirpur-01
26 M/s Thakur Enterprises, Thakur Niwas, Lower Anji, Vikasnagar, Kasumpti, Shimla-09
27 Shakti Enterprises, F123, sec-1, Manish Market, Pocket-2, Dwarka, New Delhi
28 Trig Guard Force, the Retreat Phagly-Shimla-4
29 Rapid Security Force, Kamal Kuteer, Lower Chakkar Shimla-5
30 HP Electronics Vikas Nigam, Mehli-Shimla.
31 Himalyan Gyan Vigyan Smiti Shivalik Sadan, Engine Ghar Sanjouli.
32 Pradeep Kumar Contractor VPO Sudhedh Tehsil Shahpur, Kangra
33 S.M. Man Power Services Pvt. Ltd. H/o Wrd-7, Kupper, Joginder Nagar-Mandi (HP)
34 Action Research & Training, Rajgarah, Sigmaur.
35 SM Men Power Services Pvt. Ltd-D/Shala, Kangra.
36 HPSEDC Ms. Rattan Imporium Secority Ser. Flat No-6 Aryan Deep Nalswood Shimla
37 Sunrise Education Society, Plote No-1412, Ward-4, Nangale Road Una, HP
38 Rudra Consultancy service Pvt. Ltd., Phase-III, New Shimla-
39 Him Security Placement Services MIG-31 Housing Board Colony Hamirpur-01
40 Himachal Detective Security Service Shukuntla Cottage, Nr. Petrol Pump, Chambaghat, Solan.
41 Sh. Rajesh Kumar, Govt. Contractor, man Power supplier, Vill-Belehar, PO-Yol Cantt. Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.)
42 Frontline (NCR) Business Solutions Pvt. Ltd, Branch office 3rd Floor Thakur Villa, Jal Bhawan Centre Bank Kasumpti-Shimla
43 Shakti Committee Bharmaur, Distt- Bharmaur.
44 Vishal Mahila Mandal, Moh. Hatnalla District Chamba (H.P.)
45 Social Work and Dev. Association Kundlidhar Distt. Kangra.
46 Kamna Sanstha Sirmour, Nahan Distt-Sirmour.
47 S.D.C. Menpower Services, Shell Kunj, 1st Floor, Nr HIMFED, Build. B.C.S., New Shimla-01
48 Hamirpur Outsourcing & Travel Agency Pvt. Ltd. Hamirpur.
49 M/s Corporate Care Middle Market Sect-02 New Shimla.
50 M/s Services Pvt. Ltd. H.P. SCO-I, FF, HIMUDA Complex, Sai Road Baddi, Distt-Solan (HP) 1732205
51 Naresh Kumar, Govt Contractor Vill-Hahnu, PO-Bayala, The-Sundernagar-Mandi.
52 Sh. Sanjeev Kumar & Sh. Bharat Lal, VPO Pangi, The- Kalpa, Kinnaur.
53 National Info. Science Centre Services Instt. (NICSI)-Shimla
54 HP Voluntary Health Association, B-37, New Shimla-09.
55 Nehru Yuva Kendra, Dharamshala.
56 Distt. Literacy Society Kullu.
57 Ma Saraswati Society-Palmpur
58 Soft Solution, Shimla-09.
59 HIMTECH Education-Nahan.
60 HIM Productive Instt. of Education, Lakar Bazar- Shimla
61 HPIE, Shimla Zed Security Services, Dehradun
62 Maharishi Enterprises Near Civil Hospital Dehra, Kangra, HP
63 Ramesh Kumar Contractor, Ayurvedic Colony Dharamshala.
64 M/s Baldev Kumar, Surajkund Road, Kangra, Teh & Distt-Kangra.
65 M/s Chaitanya Enterprises, Tika Lehsar, VPO Yol Cantt, Teh-Dharamshala, Kangra, HP
66 Shri Raj Kumar, House Keeping Contractor, B-7, Dev Niwas, Engine Ghar, Sanjauli-Shimla
67 M/S A.B. Enterprises Flat No. 6, Block No. 12-A, HBC- Sanjauli, Shimla-6
68 M/S J.K Enterprises Lakkar Bazar, Shimla
69 First Class Security Service (Personal) Limited, Delhi
70 Rita Contractor, Lower Arniala, PO Kotla Kalaamb, District Una.
71 M/S Arun Sharma Contractor- Rajgarh
72 M/S Universal Training and research Institute, Sanjouli Shimla
73 M/s Jagmohan Vill & P.O Charna Distt. Sirmour.
74 M/S Kuldeep Kumar Sharma V. Sajoo P.O Piploo Tehsil Dharampur
75 M/S Suresh Sharma P.O Jaladi Tehsil Nadaun Distt Hamirpur
76 M/S Bhadur Ram Vill &P.O Jia Tehsil Palampur Distt. Kangra.
77 M/S Vigilant Howk 186 Defence Colony P.O Jandwal Distt Pathankot (PB)
78 M/S Dharamshala Electrical works D/Shala
79 Sh. Partap Chand Vill Samoga PO Manjeer Distt. Chamba
80 Baldev Ram Govt Cont. Vill Luj Tehsil Pangi Distt. Chamba
81 Sh. Kedar Nath Govt. Contractor Vill. Malhiat Tehsil Pangi Distt. Chamba
82 M/S Sharma Light House HO Dehar Tehsil Sundernagar Distt. Mandi.
83 M/S Electronics and industrial institute Shimla
84 Jan Kalyan Seva Sansthan, Nerwa.
85 M/S First Grade Security service Private Limited Shimla
86 M/S Maya Enterprises VPO Toni Devi Distt Hamirpur
87 M/S Pawan Kumar Govt. Contractor Tahliwal-Una
88 M/S Anju Sharma and Sons VPO Rakkar Distt Kangra
89 The Director Society for Social Uplift though Rural Action, Jagit Nagar, Tech Kasauli, Solan
90 Manav Sewa Sansthan Berthin Distt. Bilaspur.
91 M/S S.M Man power Service Private Kangra
92 Rudra XI consultancy Services Pvt. Ltd. Janki Dass Buid. Property No. 3 The Mall Road, Shimla
93 The Chairman, Dev Bhumi Vikas Pasishad Kullu (H.P.)
94 EG Source Sol. Pvt. Ltd- Rajindra Palance,New Delhi.